# त्योहारों के अवसर पर आमजन को पौधारोपण के लिए प्रेरित करें- भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा की व पौधों की उचित देखभाल के निर्देश दिए

जयपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि "हरियालो राजस्थान" अभियान के तहत इस वर्ष भी 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएं। उन्होंने विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि समन्वय के साथ पौधे लगाएं एवं उनकी उचित देखभाल भी की जाए। साथ ही, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस वर्ष भी हरियालो राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है तथा अब तक 7 करोड़ 58 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं।**

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में "हरियालो राजस्थान" अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली।*

मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि अब तक 7 करोड़ 58 लाख से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को भी त्योहारों के अवसर पर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने आमजन से रक्षाबंधन के अवसर पर एक पेड़ भाई-बहन के नाम पर लगाने का आव्हान भी किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर पौधारोपण करने वाले भाई-बहनों को सम्मानित भी किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा राजेश कुमार यादव, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल सहित, विभिन्न अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

## टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

नई दिल्ली, 25 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग पर सुनवाई करते हुए 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।

याचिका तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर की है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि वे लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पेश होंगे। मेहता ने कहा कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए हैं। याचिका में बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर फैसले में हो रही देरी को चुनौती दी गई है।

### 'नीट प्रदर्शन ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

याचिका का जोरदार विरोध करते हुए इसे बेहद शरारतपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, मांग यह है कि आपकी बनाई समिति का पुनर्गठन किया जाए और किसी मंत्री वगैरह की जांच की जाए।

### केन्द्र सरकार ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

बफर स्टॉक का भी इस्तेमाल कर रही है और जरूरत पड़ने पर इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।

# पीटीआई में फर्जी डिग्री प्रकरण में कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

## एसओजी ने फर्ज़ी व बैकडेटे बीपीएड डिग्री के मामले में मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय पर कार्यवाही की

जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और बैकडेटेड बीपीएड डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री की भर्ती परीक्षाओं में ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की जांच आईजी अजय पाल लाम्बा, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में की जा रही है।

जांच में सामने आया कि सांचौर जिले के धानता निवासी अभ्यर्थी भारमल राम ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा दी थी। आवेदन के समय उसने ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू की डिग्री का उल्लेख किया था, जबकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान मध्यप्रदेश के श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री प्रस्तुत की।

- **जाँच के अनुसार, सांचोर जिले के भारमल राम ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा दी। आवेदन के समय उसने ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू की डिग्री का उल्लेख किया, पर दस्तावेज सत्यापन के समय श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री प्रस्तुत की।**

एसओजी ने न्यायालय से वारंट लेकर विश्वविद्यालय में तलाशी ली और कंप्यूटर डेटा जब्त किया। फॉरेंसिक वित्तीय ऑडिट में भारमल राम के नाम से फीस के दो अलग-अलग लेज़र खाते सामने आए। जांच में यह भी पाया गया कि परीक्षा परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था, जबकि फीस से संबंधित प्रविष्टियां बाद की तारीखों में बैकडेट करके दर्ज की गई थीं।

एसओजी की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय में बीपीएड की 100 सीटें स्वीकृत हैं। इसके बावजूद पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में 66 अभ्यर्थियों ने इसी विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री प्रस्तुत की। जांच एजेंसी को आशंका है कि इनमें से अधिकांश डिग्रियां बैकडेट में जारी की गईं। अब एसओजी इन सभी अभ्यर्थियों की डिग्रियों और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।

### तरुण तेजपाल ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

को सरेंडर करने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि बांबे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने अपने 6 अगस्त के फैसले में सरेंडर करने पर एक महीने की रोक रखी है। तेजपाल ने उन्हें दी गई दस साल की सजा को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। तरुण तेजपाल के पहले गोवा सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल कर तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की है।

# एच 1 एन 1 से घबराने की जरुरत नहीं है- आईसीएमआर

## आईसीएमआर महानिदेशक ने कहा कि वायरस में पाया गया अनुवांशिक बदलाव सामान्य मौसमी बदलाव है

नई दिल्ली, 25 अगस्त। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ ते मामलों के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर ) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक और डीएचआर सचिव डॉ. राजीव बहल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है।

डॉ. राजीव बहल के अनुसार, यह वायरस वंशावली भारत में साल 2025 से लगातार प्रसारित हो रही है। वायरस में पाए गए आनुवंशिक बदलाव सामान्य मौसमी बदलाव हैं, जिन्हें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से किसी नए या अधिक खतरनाक वायरस के उभरने का संकेत नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों में, सही देखभाल, भरपूर आराम और शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने से लक्षण बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ़ एच1एन1 होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाएगी या उसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी।

- **डॉ. राजीव बहल ने कहा कि ज्यादातर लोगों में सही देखभाल, भरपूर आराम और शरीर में पानी सही मात्रा रखने से लक्षण बेहतर हो जाते हैं।**

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मौसमी इन्फ्लुएंजा, जिसमें एच1एन1 भी शामिल है, स्वस्थ लोगों में आमतौर पर हल्का और स्व-सीमित संक्रमण होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं। हालांकि, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में जटिलताओं का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह दी गई है। सरकार ने लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढंकने, नियमित रूप से हाथ धोने, बीमार होने पर घर पर रहने, पर्याप्त पानी पीने और आराम की सलाह दी है।

## राम रहीम को फिर 21 दिन की फरलो मिली

रोहतक, 25 अगस्त। यौन शोषण और हत्या मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है, जिसके बाद मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे जेल से बाहर निकाला गया और वह सिरसा के लिए रवाना हो गया। गुरमीत राम रहीम 17वीं बार रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल या फरलो पर बाहर आया है। गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में साध्वियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनारिया जेल भेजा गया था। इसके अलावा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उसे सजा हो चुकी है। वर्ष 2026 में राम रहीम को इससे पहले दो बार जेल से बाहर आने का अवसर मिला। अब एक बार फिर 21 दिन की फरलो मिलने के बाद राम रहीम जेल से बाहर आया है। राम रहीम के 17वीं बार जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उसकी पैरोल और फरलो को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

# डीआरडीओ की मिसाइल टैक्नॉलजी स्वदेशी रक्षा उद्योग को ट्रांसफर होगी

## सरकार के इस फैसले से मिसाइल प्रणाली का विकास औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित होगा

नई दिल्ली, 25 अगस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टैक्नॉलजीज़ को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेश में ही उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ ने की दिशा में इस फैसले से भारतीय कंपनियों को रेगुलेटरी नियमों का पालन करने वाले एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम बनाने में बढ़ ावा मिलेगा। घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके सरकार न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ ावा दे रही है, बल्कि देश के डिफेंस सेक्टर को भी बेहतर बना रही है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करना संभव होगा। इससे उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और विनिर्माण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करना, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करना और आपूर्ति श्रृंखला में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों की भागीदारी के अवसर उत्पन्न करना है।

इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता घटाना तथा गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ ावा देने के साथ ही, भारत के डिफैंस मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। डीआरडीओ उन्नत डिफैंस टैक्नॉलजीज़ के हस्तांतरण, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढ ालने और रक्षा प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ाने के फैसले से घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा देश का डिफेन्स सैक्टर बेहतर बनेगा।**

प्रौद्योगिकी का यह हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर रक्षा क्षेत्र के अनुकूल परिवेश में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पहल के तहत घरेलू कंपनियां डीआरडीओ के मानकों पर मिसाइल सिस्टम बना पाएंगी।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ के बनाए मिसाइल सिस्टम का घरेलू उत्पादन शुरू करने के इस कदम का मकसद आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू वैल्यू एडिशन का हिस्सा बढ़ ाना और भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना है।

### क्रीमी लेयर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि इस फैसले को लागू करने से बड़े स्तर पर असर पड़ सकता है।

इसके तहत उन उम्मीदवारों को भी गैर क्रीमी लेयर माना जा सकता है, जिनके माता-पिता की आय अधिक है। सरकार ने मांग की है कि इसके लिए दो साल का समय दिया जाए, ताकि इस दौरान उन पदों की समानता तय करने की जरुरी प्रक्रिया पूरी की जा सके।

# दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले आतंकी हमले की आशंका

नई दिल्ली, 25 अगस्त। राजधानी में 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठा आतंकी शहजाद भट्टी दिल्ली के बाहरी इलाकों में कम तीव्रता वाले विस्फोट करने या पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच सकता है।

इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ ा दी है और एहतियाती तौर पर दो हजार से अधिक लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, निगरानी के दायरे में घोषित अपराधी, जमानत पर बाहर चल रहे संदिग्ध और सबूतों के अभाव में रिहा किए गए ऐसे लोग शामिल हैं, जिनकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं।

- **खुफिया इनपुट पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई, दो हजार लोगों की गतिविधियों पर नजर**

अधिकारी के मुताबिक, खुफिया जानकारी का विश्लेषण इस आशंका की ओर इशारा करता है कि सम्मेलन के दौरान दहशत फैलाने और सुर्खियां बटोरने के उद्देश्य से कम तीव्रता वाला हमला किया जा सकता है।

उनके मुताबिक, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सम्मेलन स्थल और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा पहले से कड़ी है, लेकिन राजधानी के हर हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित रखना संभव नहीं है। ऐसे में बाहरी और सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

एक अन्य इनपुट में दिल्ली समेत एनसीआर में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि भट्टी इस साजिश को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े लोगों की मदद ले सकता है।

यह अलर्ट भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ हाल में देशभर में हुई कार्रवाई के बाद सामने आया है। केन्द्र सरकार के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस से पहले इस सिंडिकेट से जुड़े 200 से अधिक संदिग्ध गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था।

### प्र.मंत्री न तो ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अमेरिका में वे संघ के प्रवासी भारतीय नेटवर्क के साथ विचार-विमर्श करेंगे। वहां होने वाली बैठकों और विचार-मंथन के बाद मोहन भागवत आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि मोदी-शाह की जोड़ी से कैसे निपटा जाए और ऐसी स्थिति में, जब मोदी के लिए राजनीतिक परिस्थितियां मुश्किल हों, सरकार के संचालन में संघ की भूमिका को एक महत्वपूर्ण निर्णायक शक्ति के रूप में कैसे स्थापित किया जाए।

# कांग्रेस ने सोच समझकर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कोशिश की, जो उनके अनुसार, भाजपा-आरएसएस की उस सोच को चुनौती दे रही है, जिसमें महिलाओं को सीमित और नियंत्रित रखने की अपेक्षा की जाती है।

6 अगस्त को राहुल द्वारा छात्रों के लिए आयोजित इंस्टाग्राम के 'आस्क मी एनीथिंग' कार्यक्रम के साथ पुणे के आयोजन को देखा जाए तो कांग्रेस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर अपनी रणनीति काफी हद तक तय कर ली है।

कांग्रेस ने निष्कर्ष निकाला है कि वह सीजेपी को उसके ही खेल में नहीं हरा सकती, न ही उसके साथ खड़ी होगी। इसके बजाय पार्टी ने उस संचार रणनीति से सीख लेने का फैसला किया है, जिसने इस नई राजनीतिक संस्था को बेहद कम समय में लोकप्रिय बना दिया।

'छात्रों की गूंज' को पारंपरिक राजनीतिक रैली की बजाय, एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी युवाओं की बातें सुनते हैं, प्रस्तुतियों और आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, युवा प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं और दर्शकों के अनुरुप अपनी भाषा में बदलाव करते हैं।

कांग्रेस अब जेन ज़ैड को अलग-अलग वर्गों में बांटकर संवाद शुरू करने की दिशा में भी बढ़ रही है। मसलन, युवाओं को एक एकल राजनीतिक समूह मानने के बजाय, युवा महिलाओं जैसे विशिष्ट वर्गों के मुद्दों पर अलग बातचीत की जा रही है।

सीजेपी को खत्म करने या बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कोई 'वार रूम' रणनीति नहीं बनाई है। पार्टी की रणनीति कहीं अधिक सूक्ष्म है और जून से अगस्त के बीच कई चरणों में विकसित हुई है।

इस रणनीति के प्रमुख हिस्से हैं- सीजेपी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का समर्थन करना, राजनीतिक उपलब्धि में अपनी हिस्सेदारी का दावा करना, संगठनात्मक दूरी बनाए रखना, राहुल के नेतृत्व में समानांतर युवा मंच तैयार करना और धीरे-धीरे कांग्रेस की भाषा को उन रोजमर्रा के मुद्दों के करीब ले जाना, जिन्होंने सीजेपी को सफलता दिलाई।

हालांकि कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि यह रणनीति सीजेपी के जवाब में शुरू नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा में 'छात्रों की गूंज' शुरू की थी, यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर लम्बा आंदोलन शुरू करने से तीन दिन पहले।

कांग्रेस नेता शशि थरूर भी सार्वजनिक रूप से यह बात कह चुके हैं और यह पार्टी का मुख्य बचाव बन चुका है कि कांग्रेस ने सीजेपी के लोकप्रिय होने के बाद छात्र राजनीति की ओर रुख नहीं किया। राहुल गांधी पहले से ही परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और चरमराई परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठा रहे थे।

लेकिन सीजेपी आंदोलन के पहले महीने के दौरान, कांग्रेस ने जानबूझकर जंतर-मंतर से दूरी बनाए रखी।

इस फैसले के पीछे दो तरह की आशंकाएं थीं। पहली आशंका, जिसे उस समय पार्टी के कई पदाधिकारियों ने खुले तौर पर व्यक्त किया था, यह थी कि सीजेपी भाजपा द्वारा प्रायोजित एक ऐसा ध्यान भटकाने वाला अभियान हो सकता है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर के चंदे से जुड़े आरोपों पर कांग्रेस के अपने अभियानों को कमजोर करना हो।

# ईरान से ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इन कंपनियों को उस सूची में शामिल किया गया है, जिन पर ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन अथवा विपणन से जुड़े महत्वपूर्ण लेन-देन में जानबूझकर शामिल होने का आरोप है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने सोमवार को एक बयान में कहा, आज अमेरिका ने ईरानी शासन की अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों को सक्षम बनाने वाली कई संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है।

उन्होंने आगे कहा कि "इन गतिविधियों में इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों और सहयोगियों पर हमले, अवैध हथियारों की खरीद, अमेरिकी बुनियादी ढांचे में साइबर घुसपैठ तथा ऊर्जा उत्पादों और थोक धन के ऐसे हस्तांतरण शामिल हैं, जिसमें दुनियाभर में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

अब देखना यह है कि मोदी सरकार ट्रंप प्रशासन की इस खुली दबंगई के खिलाफ विरोध दर्ज कराती है या फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुककर इस चोट को भी चुपचाप सहन कर लेती है।

# अमेरिका और चीन के संबंध ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

और अपने अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।" उन्होंने संकेत दिया कि अगर वॉशिंगटन चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो बीजिंग जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

इसके बावजूद, चीन के लिए तत्काल आर्थिक जोखिम उतना बड़ा नहीं हो सकता, जितना वॉशिंगटन उम्मीद कर रहा है। चीन के ईरान से कच्चे तेल के आयात में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है। वॉर्टेक्सा कंपनी द्वारा जुटाए और विश्लेषण किए गए तेल आवाजाही के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध से पहले ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति औसतन करीब 14 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो हाल के महीनों में घटकर लगभग 7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है।

रिफाइनरी में कम कामकाज और घरेलू स्टॉक का इस्तेमाल करने से ईरान की आपूर्ति पर चीन की तत्काल निर्भरता कम हो गई है। इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग अपनी कुल ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी तत्काल खतरे के बिना ईरान से तेल के आयात में और कमी को भी झेल सकता है।

- **चीन ने अमेरिकी दबाव को नकार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन अपने अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। संकेत साफ है कि चीन भी जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार है।**

एक स्वतंत्र ऊर्जा अनुसंधान और परामर्श कंपनी रिस्टैड की तियान्यू हू के अनुसार, ईरान से कच्चे तेल के आयात को "पूरी तरह रोकने" का चीन की तेल सुरक्षा पर शायद ही कोई बड़ा या तुरंत असर पड़े, क्योंकि ईरान से तेल की खरीद पहले ही काफी कम हो चुकी है और चीन के पास अभी भी कच्चे तेल का अपेक्षाकृत बड़ा भंडार है।

लेकिन वॉशिंगटन के लिए मामला केवल चीन की ऊर्जा सुरक्षा का नहीं है। मुद्दा ईरान की सरकार और सेना को आर्थिक रूप से चलाने वाली आय के मुख्य स्रोत को बंद करना है।

इससे ट्रंप प्रशासन के सामने एक मुश्किल रणनीतिक फैसला खड़ा हो गया है। अगला कदम चीनी "टीपॉट" रिफाइनरियों (छोटी और स्वतंत्र तेल रिफाइनरियाँ), तेल कारोबारियों, शिपिंग कंपनियों और ईरान के कच्चे तेल का कारोबार करने वाले अन्य बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाना हो सकता है। ऐसे कदमों से चीनी वित्तीय व्यवस्था पर सीधे हमला किए बिना बीजिंग पर दबाव बढ़ाया जा सकता है।

लेकिन बड़ा टकराव तब होगा, जब वॉशिंगटन बड़े चीनी बैंकों को निशाना बनाएगा या उन्हें अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से बाहर करने की धमकी देगा। इससे ईरान पर प्रतिबंध लगाने का अभियान अमेरिका-चीन के बहुत बड़े आर्थिक टकराव में बदल सकता है। इसका असर वैश्विक व्यापार और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है।

ऊर्जा के क्षेत्र में इसके नतीजे चीन से आगे भी जा सकते हैं। ईरान के तेल निर्यात में बड़ी गिरावट और साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास जारी रुकावटों के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। चीन खुद इस समुद्री मार्ग में किसी भी रुकावट से खास तौर पर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उसके तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (लिक्विफाइड नैचुरल गैस) के आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है।

कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर अमेरिका, भारत और तेल आयात करने वाले अन्य बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं के लिए ईंधन लागत पर भी पड़ेगा।

इसलिए ट्रंप प्रशासन के सामने एक नाज़ुक संतुलन बनाने की कठिन चुनौती है। उसे चीन पर इतना दबाव डालना है कि ईरान की तेल से होने वाली आय को रोका जा सके, लेकिन इतना ज्यादा दबाव भी नहीं डालना है कि यह अभियान बीजिंग के साथ पूर्ण आर्थिक टकराव में बदल जाए या दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर एक और बड़ा संकट पैदा हो जाए।

सोमवार को उठाए गए कदम फिलहाल व्यापक टकराव की शुरुआत के बजाय, चेतावनी देने वाले कदम लगते हैं। लेकिन अगर वॉशिंगटन चीन की बड़ी तेल कंपनियों या बैंकों के खिलाफ अगला कदम उठाता है, तो ईरान का युद्ध तेजी से अमेरिका-चीन के बीच बड़े आर्थिक टकराव का रूप ले सकता है।

राष्ट्रदूत ( एच.यू.एफ. ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908